E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2022; 5(1): 348-351
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 03-02-2023
Accepted: 18-03-2023

राम चरण गुर्जर
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
राम चरण गुर्जर
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान, भारत

पाकिस्तान का वर्तमान राजनीतिक संकट और अतीत की जड़े, मुद्दे और समाधान : एक विश्लेषण

राम चरण गुर्जर

सारांश
एक देश में स्वस्थ–नागरिक सैन्य संबंध केवल वोट डालने, सरकार के मुखिया को चुनने अथवा विधायिका के अस्तित्व के होने भर से ही सुनिश्चित नहीं होते अपितु यह लोकतान्त्रिक–नागरिक संस्था निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए व्यापक राजनीतिक जागरूकता व शिक्षा, संवैधानिक शासन, नागरिक–स्वतंत्रता, कानून का शासन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि व्यवस्थाओं को अपनाना आवश्यक है। इन सब के बिना चाहें कोई भी शासन हो लोकतंत्र को उसके वास्तविक अर्थों में व्यवहार में नहीं ला सकता। पाकिस्तान की वर्तमान समस्या का मूल कारण भी स्वस्थ्य नागरिक–सैन्य संबंधो का अभाव ही है, जिसकी जड़े पाकिस्तान के इतिहास में छिपी हुई है। अतीत में पाकिस्तान के सैन्य और नागरिक शासकों की अलोकतांत्रिक व सत्तावादी शासन की प्रकृति के कारण ही, पाकिस्तान आज इस अस्थिरता के संकट से गुजर रहा है। क्योंकि यहाँ के शासकों ने संविधानिक प्रक्रिया और कानून के शासन को बहुत कम सम्मान दिया है।

मूल शब्दः नागरिक–सैन्य संबंध, संवैधानिक शासन, तख्तापलट, सैन्य–शासन, मानवाधिकार, राजनीतिक–संस्कृति।

प्रस्तावना
पाकिस्तान संवैधानिक रूप से एक लोकतांत्रिक संसदीय गणतंत्र है, जिसकी राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार शासन का निर्धारण निर्वाचन के आधार पर होता है। लेकिन अनेक वर्षों से, देश लगातार मार्शल लॉ के अंतर्गत रहा है। मार्शल लॉ उस स्थिति को कहते है जब सेना देश के सभी घरेलू एवं विदेशी मामलों को पूर्णतः अपने हाथ में ले लेती है। यह अवधारणा पाकिस्तान के लिए कोई नई नहीं है, यहाँ चार अलग–अलग सैन्य शासकों के अधीन तीन बार सैन्य तख्तापलट की परिघटना हो चुकी है।

पाकिस्तान पहली बार 1958 में तब सैन्य शासन के अधीन आया जब राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने संविधान को रद्द कर दिया और जनरल अयूब खान को मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक नियुक्त करके देश में मार्शल लॉ घोषित कर दिया, कुछ हफ्ते बाद अयूब खान को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया। यद्धपि पकिस्तान का यह पहला मार्शल लॉ आधिकारिक रूप से 44 महीने तक ही चला लेकिन जनरल अयूब खान ने जब 1969 में अपना पद छोड़ा तो जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। इस प्रकार देश 1958 से 1971 तक सैन्य शासन के अधीन रहा। अयूब खान की तरह, जनरल याहया खान भी मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक बने। 1971 के युद्ध में भारत से शर्मनाक हार व भारी नुकसान के बाद,जनरल अयूब खान के विपरीत जनरल याह्या खान अपने उत्तराधिकारी का चयन करने में असफल रहे और ऐसे में उनके उत्तराधिकारी के रूप में देश के पहले आम चुनावों में पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को जनमत की मांग पर राष्ट्रपति बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

दूसरा सैन्य तख्तापलट 1977 में हुआ जब जनरल जिया उल हक और उनकी सेना ने संसद को भंग कर दिया और भुट्टो को नजरबंद कर दिया। जिया उल हक शुरू में एक निष्पक्ष चुनाव का वादा करके सत्ता में आया लेकिन जल्द ही यह महसूस हो गया कि जिया का सत्ता छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। जनरल जिया उल हक ने अंततः 1985 में मुहम्मद खान जुनेजो को देश के नए प्रधान मंत्री चुनने के बाद इस्तीफा दे दिया, इस तरह मार्शल लॉ के तहत पाकिस्तान का दूसरा अनुभव समाप्त हुआ।

तीसरा और आखिरी सैन्य तख्तापलट 1999 में हुआ जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल कर दिया। कारगिल से पाकिस्तानी सेना के पीछे हटाने के कारण शरीफ पहले से ही देश में प्रतिक्रिया का सामना कर रहे थे। एक सैन्य तख्तापलट की संभावना को भांपते हुए, शरीफ ने मुशर्रफ को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाने का प्रयास किया,

लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि सेना ने खुद मुशर्रफ का पक्ष लिया और इसके बदले मुशर्रफ ने, शरीफ को ही उसके पद से हटा दिया और उसकी जगह ले ली। मुशर्रफ ने आखिरकार 2008 में इस्तीफा दिया और आसिफ अली जरदारी के नए राष्ट्रपति बनने के साथ पाकिस्तान के आखिरी सैन्य–शासन की समाप्ति हुई।

2010 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने 18वां संविधान संशोधन को पारित किया। इस संशोधन के द्वारा बहुत सारे बदलावों को लागू किया लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में, इसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा संसद को एकतरफा रूप से भंग करने की शक्ति को समाप्त कर दिया और पाकिस्तान को अब एक अर्ध–राष्ट्रपति से संसदीय गणराज्य में बदल दिया। इस तरह के बड़े बदलाव को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पाकिस्तान अब किसी भी तरह के सैन्य तख्तापलट की संभावना को टालकर लोकतांत्रिक दिशा में आगे बढ़े। तब यह मान लिया गया था कि इस संशोधन के परिणामस्वरूप सेना की शक्ति तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगी तथा पूरी तरह से सेना के पास होने वाली शक्ति को अन्य लोकतांत्रिक निकायों (अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने इसके बाद निर्वाचित सरकारों के बीच सत्ता का एक लोकतांत्रिक परिवर्तन देखा है, लेकिन अभी भी निर्णय निर्माणकारी निकायों पर सेना का प्रभाव हाल के घटनाक्रमों से पूर्णतः स्पष्ट होता है, यह बताता है कि सेना का प्रभाव विभिन्न तरीकों से एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों में विस्तृत हो गया है।

एक आधुनिक 'लोकतांत्रिक' शासन की आड़ में सैन्य शासन–

पाकिस्तान में लोकतंत्र का सवाल हमेशा पेचीदा रहा है। लेखक और राजनीतिक टिप्पणीकार वुसतुल्लाह ख़ान का मानना है कि देश में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था, लोकतंत्र के अलावा कुछ भी है। सैद्धांतिक तौर पर यह दावा किया जा सकता है कि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हर कोई जानता है कि सही मायने में ऐसा नहीं है।

पाकिस्तान के आखिरी आम चुनाव 2018 में पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान के विजयी होने के साथ हुए थे। हालांकि खान बहुमत के साथ सत्ता में आए, लेकिन विपक्ष ने इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया। 2020 में विपक्षी दलों ने पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) नामक एक गठबंधन का गठन किया,पीडीएम का उद्देश्य सरकार के खिलाफ देशव्यापी रैलियां और विरोध प्रदर्शन करना था। इस गठबंधन के सदस्यों को लगता था कि आम चुनावों में धांधली हुई थी और इमरान खान पूरी तरह से सेना की वजह से सत्ता में आए थे, उनका मानना था कि पीटीआई सरकार को 'क्षद्म स्थिरता' प्रदान कर रही है। साथ ही वे मानते थे कि सेना ने एक 'कठपुतली सरकार' को सत्ता में लाने के लिए चुनावों में हस्तक्षेप किया जिसके माध्यम से वे देश को नियंत्रित कर सकते हैं। अंत में, विपक्षी दलों ने भी देश के आंतरिक मामलों में सेना की भागीदारी पर अपनी 'अत्यधिक चिंता' व्यक्त की; सेना के हस्तक्षेप का एक उत्कृष्ट उदाहरण तब देखा गया जब सीओएएस जनरल बाजवा ने पाकिस्तान में किसान नेताओं और व्यापारियों से मुलाकात की और उन्हें समय पर अपने करों का भुगतान करने और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए निर्यात बढ़ाने के लिए राजी किया। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जनरल बाजवा को देश के बारे में वित्तीय निर्णय लेने की शक्ति थी जो एक लोकतांत्रिक देश में सेना की भूमिका के रूप में बिल्कुल अस्वीकार्य है।

गैर–रक्षा–संबंधित मामलों में सेना के हस्तक्षेप और जनरल बाजवा के पास मौजूद शक्तियों का एक और उदाहरण तब उजागर हुआ जब बाजवा को सीओएएस के रूप में 3 साल का विस्तार दिया गया। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में वैधता पर सवाल उठाए गए और यह विषय अत्यधिक विवादास्पद हो गया। 28 नवंबर 2019 को, **सर्वोच्च न्यायालय** ने बाजवा के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने का फैसला सुनाया और संसद को इससे संबंधित प्रक्रिया के लिए सेना अधिनियम और 1973 के संविधान में संशोधन कर 'नए नियम बनाने' का आदेश दिया। इससे साफ पता चलता है कि थल सेना प्रमुख के खिलाफ न्यायपालिका भी अपना स्वतंत्र पक्ष नही रख सकती थी। यह उदाहरण पाकिस्तान के समग्र राजनीतिक और सामाजिक पतन को भी दर्शाता है, जहां एक आदर्श लोकतांत्रिक राज्य में न्यायपालिका को कानून के शासन को बनाए रखने और लोगों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने तथा उनकी रक्षा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्था माना जाता है।

जब जुलाई 2018 में पीटीआई सरकार सत्ता में आई तो, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी द्वारा विभिन्न अभियान चलाए गए, जिनमें पाकिस्तान के लिए एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली के रूप में राष्ट्रपति प्रणाली की वापसी की वकालत की गई थी। जून 2021 में, ट्विटर पर एक उर्दू हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, जिसका अनुवाद था "पाकिस्तान में राष्ट्रपति तंत्र की बहाली एकदम नजदीक है"। इसका एक मतलब यह है कि इमरान खान की सरकार का एक एजेंडा संविधान के 18वें संशोधन को रद्द करना था, जिसने 2010 में संसद को एकतरफा भंग करने की राष्ट्रपति की शक्ति को छीन लिया था। इस संशोधन से तब सेना को छोड़कर सभी को लाभ हुआ था, इसने सैन्य नेताओं की क्षमता और यहां तक कि देश पर प्रत्यक्ष–शासन करने में सक्षम होने की आकांक्षा को भी समाप्त कर दिया था। लिहाजा पीटीआई का राष्ट्रपति प्रणाली वापस लाने की मंशा किसी और के लिए नहीं बल्कि सेना की स्थिति को मजबूत करने के लिए थी।

कई सालों तक पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान को ये लगता रहा कि इमरान ख़ान के रूप में उन्होंने देश का रक्षक खोज लिया है, लेकिन सत्ता से बाहर रहने के एक साल के भीतर ही वो पाकिस्तान की सेना के दुश्मन नंबर वन बन गए। पाकिस्तान की सेना इमरान ख़ान से निबटने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ का देशभर में दमन किया जा रहा है।

पाकिस्तान में, आमतौर पर सभी प्रधानमंत्री सेना से अलग हो ही जाते हैं। ये किसी प्रथा के जैसा है. देश के पहले चुने हुए प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया था। उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो को प्रधानमंत्री के पद से दो बार हटा दिया गया था और एक युवा हमलावर के हाथों उनकी हत्या की कभी ठीक से जांच ही नहीं हो पाई। नवाज शरीफ को भी पद से हटा दिया गया था, उन्हें जेल भेजा गया और देश निकाला दिया गया– अब फिर से वो देश के बाहर हैं। इमरान ख़ान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने वो किया जो पहले कोई मुख्यधारा का राजनीतिक दल नहीं कर सका था. सड़कों पर प्रदर्शन करने के बजाए उन्होंने सीधे सैन्य छावनियों पर धावा बोल दिया और पाकिस्तान के आम नागरिकों को दिखाया कि पाकिस्तान की सेना के जनरल किस तरह, बड़े–बड़े बंगलों में ऐश–ओ–आराम के साथ रहते हैं।

पाकिस्तानी सेना ने ऐतहासिक रूप से राजनीति में किसी भी भूमिका से इनकार किया है। हालांकि, पिछले साल अपने रिटायरमेंट से पहले पूर्व सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा ने अप्रत्यक्ष तौर पर हस्तक्षेप की बात को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि सेना ने अतीत से सबक लिए हैं और अब आगे गैर–राजनीतिक रहने का फैसला किया है।

टिप्पणीकार वुसत का मानना है कि "सब जानते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र एक दिखावा है। पाकिस्तान के पास

संसद है, संस्थाएं हैं, एक चुनाव प्रणाली और संसाधन हैं लेकिन लोकतंत्र की आत्मा नहीं है और न ही कभी रही है।"

वर्तमान सियासी परिघटना का अंत कब होगा?

इमरान ख़ान को पहले सत्ता से हटाया गया और फिर सत्ता वापस पाने के लिए उन्होंने देशभर में आंदोलन की अपील की. उसके बाद उनके समर्थकों और सुरक्षाबलों के बीच हुई झड़पों ने देश में गंभीर संकट पैदा कर दिया।

लोकतंत्र के संदर्भ में हालात तब और भी ख़राब हुए जब 9 मई को इमरान ख़ान को इस्लामाबाद में गिरफ़्तार किया गया था।

गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सेना के ठिकानों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर अपना गुस्सा निकाला और इमरान ख़ान की रिहाई की मांग की। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम ने सेना को जनता के बीच अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने का मौका दे दिया है और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बाजी पलट गई है और इमरान ख़ान बैकफुट पर हैं। पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं, उनके समर्थकों और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, गिरफ्तारी की गई और मुक़दमा चलाया गया। अभी इनमें से कुछ लोगों पर सैन्य अदालतों में मुक़दमा भी चलने वाला है।

ऐसी स्थिति के बीच पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति और लोकतंत्र के भविष्य को लेकर अंतरराष्ट्रीय जगत में एक चिंता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पाकिस्तान के घटनाक्रमों पर चिंता जताई है। इस संकट का अल्पकालिक समाधान के रूप में आगामी आम चुनाव ही एक उम्मीद हो सकते है, लेकिन इसके लिए भी देश की लोकतान्त्रिक ताकतों को एक साथ आना ही होगा और सेना को विश्वास में लेना होगा।

लेकिन दीर्घकालिक तौर पर, पाकिस्तान की समस्या एक सतत और व्यापक राजनीतिक–आर्थिक मुद्दा है। पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक संकट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जानकार मानते हैं कि राजनीतिक उथल–पुथल ने भले ही सीधे तौर पर आर्थिक संकट पैदा न किया हो, लेकिन इसे बढ़ाया जरूर है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ पिछले साल अप्रैल में इमरान ख़ान के सत्ता से हटने तक जीडीपी 6 फीसदी थी. जबकि चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 0.6 फीसदी तक रहने का अनुमान हैं।

हमजा अलवी (1972) का मानना है कि पाकिस्तान में जमींदारों, सेना व नौकरशाही के बीच सत्ता का गठजोड़ मौजूद है, जिसे वह "मैट्रोपोलियन केपिटल" कहते हैं, जो पाकिस्तान की औपनिवेशिक विरासत व ऐतिहासिक क्रम–विकास पर आधारित, एक "अतिविकसित" उत्तर औपनिवेशिक राज्य और अविकसित समाज का परिणाम है।

पाकिस्तान की राजनीतिक संस्कृति में निर्वाचित सरकार में, सेना के हस्तक्षेप को सहज स्वीकार्यता और इसका प्रभाव

जैसा कि परिचय में उल्लेख किया गया है, पाकिस्तान पर तीन अलग–अलग सैन्य तख्तापलट के तहत चार बार अलग–अलग सैन्य शासकों द्वारा शासन किया गया , जो हमें आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करता है कि अब तक के इतिहास में पाकिस्तान में किसी भी पीढ़ी ने पूर्ण लोकतांत्रिक शासन नहीं देखा है, सेना ने हमेशा इसमें दखल दिया है इसलिए वहां के लोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन हस्तक्षेपों और नियंत्रण को स्वीकार करने लगे है।

पाकिस्तान की राजनीतिक जानकार आयशा सिद्धीकी ने अपने लेख में पाकिस्तान की राजनीति को कमजोर करने वाली कई प्रवृत्तियों पर चिंता व्यक्त की जैसे कि पाकिस्तान में लोगों ने महत्वपूर्ण मामलों जैसे भोजन और बुनियादी सुविधाओं की कीमत बढ़ने, कानून एवं व्यवस्था की बदहाली आदि पर, सरकार के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करना और विरोध करने की संस्कृति को लगभग बंद कर दिया है। सिद्दीकी इस सब के लिए दशकों की 'संरक्षण राजनीति' को दोषी मानती हैं जिसने देश में राजनीति को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का काम किया । सिद्दीकी ने बताया कि कैसे 2019 में अर्थव्यवस्था में गिरावट और बढ़ती मुद्रास्फीति के बावजूद संरक्षण की राजनीति ने लोगों को विरोध करने और राजनीतिक आंदोलनों का संचालन करने की उनकी क्षमता से वंचित कर दिया।

इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक अनुभव की कमी और अतीत में संरक्षण राजनीति की अधिकता ने पाकिस्तान के नागरिकों की अपेक्षाओं और वहाँ की राजनीति–संस्कृति पर सीधा असर डाला है।

सेना, क्यों सत्ता पर से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहती

सैद्धांतिक दृष्टि से बात करें तो, कोई भी व्यक्ति, एक ऐसी सेना से, देश की सत्ता से अपना राजनितिक नियंत्रण छोड़ने की अपेक्षा नहीं करेगा जिसने अपने गठन के बाद से ही शक्ति–आधिक्य का लाभ लिया हो और पूरे देश पर नियंत्रण रखा हो, यह मानना की सेना एकाएक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण 'लोकतंत्र' जैसी प्रणाली को सौंप देगी जो उसके विचार में एक ख्याली और अवास्तविक व्यवस्था है, बेहद अव्यावहारिक उम्मीद है।

लेकिन असली समस्या लोकतंत्र नहीं है, बल्कि सैन्य–अभिजात वर्ग का यह मानना है कि अतीत में राजनीतिक नेता सुशासन देने में हमेशा विफल रहे हैं, और सेना ही इस कार्य को करने में सक्षम है। सेना के मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक अहसान आई बट ने 'जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी' के लिए लिखे रिसर्च पेपर में पाकिस्तान की राजनीति में सेना के दखल पर अपने तर्क रखे हैं. उनका कहना है कि राजनीति में पाकिस्तानी सेना का हस्तक्षेप इस विश्वास से उपजा है कि नागरिक शासन भ्रष्ट और अदूरदर्शी हैं. अगर देश को राजनेताओं के भरोसे छोड़ दिया जाता है तो यह विनाशकारी होगा। एक बार जब सेना को मार्शल लॉ या आपातकालीन प्रावधानों की आड़ में उच्च राजनीतिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है, तो वे ऐसी शक्तियों के परित्याग के बारे में एकदम अनिच्छुक हो जाती हैं।

पाकिस्तान मामलो के विशेषज्ञ हसन रिजवी शेख ने उन युक्तियों का उल्लेख किया है जिनके माध्यम से सेना स्वयं को सत्ता में प्रभावशाली बनाए रखती है –

1. कभी–कभी सत्तारूढ़ जनरल अपने सैन्य पद से इस्तीफा दे देते हैं और जनता का साथ लेकर अपने सैन्य–शासन को नागरिक–शासन में रूपांतरित कर लेते हैं (यह एक ऐसा उपाय है जिसे शुरू में जनरल अयूब खान ने तथा बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनाया था); या
2. सैन्य कमांडर ऐसे लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के पक्ष में होते है जो सेना के राजनीतिक दृष्टिकोण को साझा करते हो अथवा सेना एक कठपुतली नागरिक सरकार की स्थापना करने का प्रयास करती है (जैसा कि पूर्व में शुरुआती इमरान खान की पीटीआई सरकार पर आरोप लगाये गए थे); या
3. सेना बैरक अथवा पर्दे के पीछे से नागरिक सरकार पर नजर रखती हैं जिससे वह निर्वाचित सरकार पर सेना की पसंद की नीतियां अपनाने के लिए दबाव डाल सके (ताकि सेना की वर्तमान की अपेक्षाओं का पूरा ख्याल रखा जाए)।

निष्कर्ष एवं संकट का संभावित समाधान

जन–साधारण में सेना के वर्चस्व के खिलाफ व्यापक विरोध की संस्कृति और लोकतान्त्रिक ताकतों का एकसाथ आना तथा नागरिकों में अपेक्षाकृत सक्षम, कुशल व जनकेंद्रित नागरिक–सरकार की उम्मीद ही वह दीर्घकालिक समाधान हो

सकते है जो पाकिस्तान को किसी वास्तविक समाधान की तरफ ले जा सकते है। एक संगठित और मजबूत सिविल सोसाइटी इस जन आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जो अभी पाकिस्तान के संदर्भ में स्पष्ट नजर नहीं आतीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तानी सेना को पाकिस्तान में विपक्षी दलों एवं जनता से काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सेना के ऊपर दबाव में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है। लेकिन भविष्य की संभावना के रूप में सेना अभी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ही खड़ी नजर आएगी जिसका कारण है–

1. सेना के पास कोई अन्य संभावित नेता नहीं है जो शहबाज की जगह ले सके।
2. मुस्लिम लीग एन ही वर्तमान में एकमात्र ऐसी बड़ी पार्टी प्रतीत होती है जो सेना के साथ इमरान खान के खिलाफ अन्त तक खड़ी रह सकती है।

अब यह समझने का समय आ गया है कि पाकिस्तानी सेना एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र को बनाए रखने में कोई भूमिका नहीं निभा सकती है और न ही निभाएगी। लेकिन, निकट भविष्य में, इसकी बहुत कम संभावना है कि सेना की शक्ति कम हो जाएगी, वास्तव में, सेना अपनी शक्तियों को बढ़ाने और पाकिस्तान की राजनीति पर प्रभाव बढ़ाने के लिए नए तरीके खोजेगी जैसा कि वह अभी कर रही है। सत्ता में मौजूदा 'हाइब्रिड शासन' एक बहुत बड़ी और दूरगामी योजना की शुरुआत है जिसमें सेना को अपनी सर्वोच्च राजनीतिक शक्तियों को फिर से हासिल करना शामिल है।

अल्पकालिक समाधान के रूप में आगामी आम चुनाव भी एक उम्मीद हो सकते है, लेकिन इसके लिए भी देश की लोकतान्त्रिक ताकतों को एकसाथ आना ही होगा। राजनीतिक विश्लेषक सलमान गनी कहते हैं, इस समय एक व्यापक राष्ट्रीय संवाद और सहमति की जरूरत है कि चुनाव बाद कैसे आगे बढ़ा जाएगा. वरना पुरानी कहानी ही दुहराई जाएगी कि जो लोग हारेंगे वो नतीजे स्वीकार नहीं करेंगे और देश गोल गोल घूमते हुए अराजकता के और गहरे संकट में फंसता जाएगा जो अंततः अस्तित्व का संकट बन सकता है।

संदर्भ सूची

1. Ayesha Siddiqua, SOAS, 'Pakistan's Hybrid civilian & military government weakens democracy' East Asia Forum, 2020.
2. Gen. Amarjit Singh, 'Why is the army in Pakistan dangerous for democracy', The Print, 2020 October.
3. Stephen Cohen, 'Future of Pakistan', The Brookings Institutions, 2011https://www.brookings.edu/wp&content/upload¢/2016/06/01_pakistan_cohen-pdf
4. Hasan Askari Rizvi, 'The ParadoÛ of Military Rule in Pakistan', University of California Press,1984
5. https://www-bbc-com/hindi/articles/ck7k0xkpk77o
6. History of Pakistan; https://www.britannica.com/place/Pakistan/The-Muslim-League-and-Mohammed-Ali-Jinnah
7. https://www.eastasiaforum-org/2020/01/21/pakistans-hybrid-civilian-military-government-weakens-democracy/
8. https://theprint.in/opinion/the-writing-is-on-the-wall-pakistans-imran-khan-govt.is-on-the-edge-of-collapse/450521/
9. https://thediplomat-com/2021/05/signs-of-rift-between-military-and-prime-minister-imran-khan-in-pakistan/
10. Salman Rafi Sheikh, Himal Southasian magazine, 2021 https://theprint.in/opinion/why-is-the-army-in-pakistan-dangerous-for democracy-answer-goes-back-to-1947/524467/
11. https://www-business-standard.com/article/international/between-imran-military-and-islamists-pak-may-see-a-three-way-tug-of-war-120101200105_1-html
12. https://thediplomat-com/2020/07/can-imran-khan-stay-in&power/
13. Ayesha Siddiqua, Power, perks, prestige and privileges of Pak military's commercial ventures
14. https://shibbolethsp.jstor.org/start?entityID=https%3A%2F%2Fidp.iiitd.edu.in%2Fidp%2Fshibboleth&dest=https://www.jstor.org/stable/24479147&site=jstor
15. https://www.bbc-com/hindi/international-65735322